

LOK SABHA DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Vol. I First day of the Ninth Session of First Parliament No. 1
of India

I

2

LOK SABHA

Monday, 21st February, 1955

The Lok Sabha met at Ten Minutes
Past Twelve of the Clock

[MR. SPEAKER (SHRI G. V. MAVALAN-
KAR) in the Chair]

QUESTIONS AND ANSWERS

(No Questions: Part I not published)

MEMBER SWORN

Shri Benjamin Hansda (Purnea cum
Santal Parganas—Reserved—Sch.
Tribes).

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I beg to lay on the Table
a copy of the President's Address to
both Houses of Parliament assembled
together on the 21st February, 1955.

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, परं एक
वर्ष के बाद आप से कुछ कहने में फिर संसद्
में आया हूँ। मुझे खुशी है कि पिछला वर्ष,
घरलू और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की दृष्टि से,
हमारे देश के लिए काफी सफलता का वर्ष रहा
है। भारत के लोग और यह संसद् अपने कार्य पर
संतोष कर सकते हैं। किन्तु संतुष्ट हो कर बैठ
रहने का यह अवसर नहीं है। हमें अपने देश में
गहन समस्याओं का सामना करना है और

उधर मानवता के भविष्य पर फिर से युद्ध के
काले बादल मंडरा रहे हैं।

मुझे हर्ष है कि सभी दूसरे देशों से हमारे
सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण रहे हैं और कुछ देशों के साथ
मंत्री तथा सहयोग की भावना में और भी अधिक
वृद्धि हुई है। बहुत से देशों से सम्मान्य
नेतागण हमारे देश में आये। पिछले वर्ष हमारे
यहां पधारने वालों में कॅनेडा, इंडोनीसिया, चीन
और श्रीलंका के प्रधान मंत्री हैं। यूगोस्लाविया के
राष्ट्रपति और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का
भारत में स्वागत करने का भी हमें सौभाग्य
प्राप्त हुआ। हमारे उपराष्ट्रपति ने हमारी
सद्भावना का संदेश अमेरिका, कॅनेडा,
मॉक्सको, अर्जन्टीना, चिली, बोलीविया,
पेरू, बाजील, यूरुगावे और इटली तक पहुंचाया।
हमारे प्रधान मंत्री, मित्र के नाते, चीन, बर्मा,
इंडोनीसिया, इंडोचाइना और मिश्र गए। हाल
ही में लंदन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान
मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, जहां
संसार की शांति से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर
स्पष्टता से और मंत्रीपूर्ण ढंग से बातचीत की
गई।

तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच
किए गये समझौते का मैं विशेष रूप से जिक्र
करना चाहूंगा। इस समझौते द्वारा इन दोनों महान्
देशों के बीच मंत्री की पुष्टि हुई, जिसका
एशिया तथा संसार की शांति से इतना अधिक
सम्बन्ध है। इस समझौते में कुछ सिद्धान्तों का
प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें अधिक
व्यापक रूप दिया जा सकता है और बहुत से
देशों ने उन सिद्धान्तों को स्वीकार भी किया
है। ये पांच सिद्धान्त, जिन्हें प्रायः पंचशील कहा

[सङ्घपीत]

जाता है, ये हैं : एक दूसरे के प्रभुत्व तथा प्रादेशिक अखंडता के लिए पारस्परिक समादर, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक समता तथा लाभ और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व । इन सिद्धान्तों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ और यह आशा करता हूँ कि ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आधार बनते जायेंगे और इस प्रकार संसार भर की सुरक्षा तथा शान्ति का कारण बनेंगे ।

आलांच्य वर्ष में श्रीलंका के प्रधान मंत्री के सुझाव पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी । यह घटना थी कोलम्बो में श्रीलंका, बर्मा, इंडोनीसीया, पाकिस्तान और भारत के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन । तत्पश्चात् इसी प्रकार का एक सम्मेलन इंडोनीसीया में बांगार नामक स्थान पर हुआ । इन सम्मेलनों में उपर्युक्त देशों ने, जो एशिया महाद्वीप का बहुवृद्ध भाग हैं, अपने विचारों और उद्देश्यों को संगठित रूप से व्यक्त किया और इससे निस्संदेह शान्ति के पक्ष को समर्थन मिला । इन सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप अब एशिया और अफ्रीका के स्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इंडोनीसीया में बुलाने का आयोजन किया गया है । इन दो महाद्वीपों के देशों के विकास और विश्वव्यापी इलचलों के क्षेत्र में इनके उत्थान का यह सम्मेलन दूसरा चरण है । मेरा विश्वास है कि इसके कारण विश्वशान्ति के पक्ष को बल मिलेगा और इन देशों के बीच सहयोग और सद्भावना बढ़ेगी ।

गत वर्ष की सब से बड़ी घटना, जो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है, जेनेवा सम्मेलन था, जिसके कारण इण्डो-चाइना में युद्धबन्दी हो सकी और इंडोचाइना के राज्यों की समस्याओं को शान्तिपूर्वक सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सका । जेनेवा सम्मेलन को अनेक महत्वपूर्ण और कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा, किन्तु सांभग्य से, शान्तिपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझाने की दिशा में सम्बद्ध राष्ट्रों के प्रयत्न सफल हुए ।

इस प्रकार उस सम्मेलन ने संसार के सामने एक उदाहरण रखा है । मैं आशा करता हूँ कि दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए भविष्य में इस उदाहरण का अनुसरण किया जायगा ।

जेनेवा सम्मेलन के परिणाम-स्वरूप भारत ने इंडोचाइना में नियुक्त किये गये तीन आयुक्तों में अपने ऊपर भारी जिम्मेदारी ली है । भारत की अध्यक्षता में ये आयोग जेनेवा में किये गये निर्णयों को कार्यरूप देने में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इनका कार्य प्रशंसनीय है ।

दुर्भाग्य से कुछ झगड़े अभी भी चल रहे हैं जिनके कारण विश्वशान्ति संकट में है । इन में सबसे प्रमुख सुदूरपूर्व-सम्बन्धी, विशेष कर फारमोसा और चीन के तटीय द्वीपों सम्बन्धी, संघर्ष हैं । मेरी सरकार चीन की एक ही सरकार को मान्यता देती है और वह है लोक गणराज्य, और वह समझती है कि इस गणराज्य के दावे उचित हैं । कुछ भी हो, मुझे पूर्ण आशा है कि ये कठिन समस्याएँ आपसी बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझ सकेंगी ।

यदि हम चाहते हैं कि संसार में समझदारी का बोला वाला रहे, तो यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने का और कोई रास्ता नहीं रह गया है । न्यूक्लियर और थर्मोन्यूक्लियर शस्त्रास्त्र इस सीमा तक विकसित हो चुके हैं कि कोई भी युद्ध जिस में इनका उपयोग किया जाएगा संसार के लिए घातक सिद्ध होगा । इस आत्म-हत्या की नीति से संसार की कोई समस्या नहीं सुलझा सकती और न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है । एक उद्बुद्ध बम न केवल एक विस्तृत क्षेत्र में प्रत्येक प्राणी को मार डालता है बल्कि तीव्र विनाशकारी लहरें पैदा करता है, और विनाश लीला का प्रसार दूर दूर तक कर देता है । ऐसे घातक अस्त्रों से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं । कुछ देशों के प्रमुख सीनिकों ने निर्विवाद शब्दों में कहा है कि ऐसा व्यापक युद्ध जिस में इन अस्त्रों का उपयोग किया जाय एकदम

प्रत्यकारी होगा। मुझे आशा है कि इन अस्वों की भयानकता को दखते हुए न केवल इनका उत्पादन बन्द हो जाएगा बल्कि मानव समाज यह भी समझ लेगा कि युद्ध किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने का साधन नहीं बन सकता।

अणुशक्ति से जहाँ संसार के विनाश का भय पैदा हो गया है, वहाँ एक नवीन आशा की किरण का जन्म भी हुआ है, बशर्तकि इसका उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में किया जाए। समस्त संसार के लोगों के जीवनयापन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक साधन अणुशक्ति द्वारा जुटाए जा सकते हैं। अर्ध-विकसित देशों को उन्नत करने की दिशा में इसका विशेष महत्व है। इस लिए अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगों पर विचार करने के लिए राष्ट्र संघ ने जेनेवा में वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन किया है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। यह सम्मेलन न केवल अणुशक्ति की सम्भावनाओं पर विचार करेगा, बल्कि जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और कृषि विज्ञान की दृष्टियों से भी उस पर विचार करेगा।

शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा एक कठिन समस्या के निपटारे का एक और उदाहरण भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का भारत सरकार को सौंपा जाना है। इन बस्तियों के नागरिकों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। इस समस्या को सुलझाने में फ्रांसीसी सरकार ने जिस नीतिज्ञता का परिचय दिया उसकी मैं सराहना करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या भी इसी प्रकार शान्तिपूर्ण ढंग से जल्द ही सुलझ जायगी।

देश की आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन में से बहुत से पहले तीन वर्षों में ही प्राप्त कर लिए गए हैं। १९५३-५४ में अनाजों का उत्पादन पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य से ४४ लाख टन अधिक हुआ। कृषि उत्पादन सूचक-अंक जो १९५०-५१ में ६६ थे, १९५३-५४ में बढ़ कर ११४ हो गए। औद्योगिक उत्पादन का सूचक-अंक १९५४ में १४४ तक जा

पहुँचे, जबकि १९५२ में वे १२५ थे, जो सल्फ: स्वाधीनता के बाद सब से ऊँची थी। गत ४ वर्षों से सूचक-अंक औसतन १० प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़े हैं।

उत्पादन में सुधार हो जाने के कारण कंट्रोल भी उठा दिए गए हैं। अनाजों का अधिक उत्पादन होने से उन क्षेत्रों में जहाँ पैदावर मांग की अपेक्षा अधिक थी, भाव बहुत अधिक गिरने की प्रवृत्ति पाई गई। भावों को लाभहीन स्तर तक न गिरने देने के लिए सरकार ने निर्धारित मूल्यों पर अनाज खरीदने का निश्चय किया।

मेरी सरकार ने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को अपने सक्रिय नियन्त्रण में लेने का निश्चय किया है, विशेषकर इसलिए कि द्यूहती और पिछड़े हुए इलाकों को उधात्सम्बन्धी सुविधायें अधिक से अधिक दी जा सकें। इंडियन इंडस्ट्रियल क्रीडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन की स्थापना से, आशा है, हमारे गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र को बहुत लाभ पहुँचेगा।

सिन्धु में वैज्ञानिक खाद तैयार करने में काफी प्रगति की जा चुकी है। विगत वर्ष में विशाकापटनम् के हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने दूरी आठ-आठ हजार टन के जहाज तैयार किये और एक सात हजार टन का पोत समुद्र में उतारा। पश्चिमी बंगाल में रूपनारायणपुर की टेलिफोन केबल फैक्टरी में भी उत्पादन शुरू हो गया है। तार और डाक विभाग की इस सम्बन्ध में जितनी भी आवश्यकताएँ होंगी, उन्हें इस कारखाने द्वारा पूरी करने की व्यवस्था की गई है। पिम्प्री का पीनिसलीन कारखाना और दिल्ली का डी० डी० टी० कारखाना भी चालू होने जा रहा है और मलेशिया-विरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता पूरी करने के हेतु एक और डी० डी० टी० कारखाना खोलने का भी विचार है।

देश के इसपात और लोहे के उत्पादन में वृद्धि को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है। इस उद्देश्य से दो नये कारखाने खोलने का निश्चय किया जा चुका है। इन कारखानों का मालिक राष्ट्र होगा। एक कारखाना रूरकला

[सफ़्टपीत]

में खोला जायगा और दूसरा मध्य प्रदेश के भीलाई प्रदेश में स्थापित किया जायगा। इस दूसरे कारखाने के सम्बन्ध में सोवियत रूस की सरकार से एक प्रारम्भिक करार किया जा चुका है।

उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विकास की दृष्टि से मेरी सरकार कुटीर और छोटे उद्योगों की उन्नति को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इन उद्योगों में आधुनिक कार्य-प्रणाली का संचार करने के लिए चार विशेष प्रादेशिक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है।

हमारी महान नदी-घाटी योजनायें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। कई एक नई योजनायें भी बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं को कार्य रूप देने में हमें जनता द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, उसका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा। इन में भी कौसी योजना में जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त हुई है वह उल्लेखनीय है।

दो वर्ष से कुछ अधिक समय में ही, अक्टूबर १९५२ में चालू की गई सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर की ईहाती जन संख्या का पांचवां हिस्सा आ चुका है। इस समय इस कार्यक्रम से ८८,००० ग्राम लाभ उठा रहे हैं और इस से कृषि, पशु सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, आशा है, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त देश आ चुकेगा। इस कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जनता में सहयोग और उत्साह का संचार हुआ है, उन में एक नवीन जागृति आई है और वे मिल जुल कर सब के हित के लिए काम करने में विश्वास करने लगे हैं।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केंद्र और राज्यों में उन्नति तथा सार्वजनिक व्यव में क्रमिक वृद्धि हुई है। अभाव-गस्त क्षेत्रों में सुधार की दिशा में स्थायी कार्य तथा ईहातों और शहरों

में पानी और बिजली की व्यवस्था को विशेष महत्त्व दिया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण का कार्य अभी आरम्भ हुआ है। पहली योजना की अपेक्षा इस योजना के अधिक व्यापक होने की आशा है। खयाल है कि इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना, रोजगार के विस्तार और शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन पर अधिक बल दिया जाएगा।

आन्ध्र राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाने से जिस में संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन कार्य नहीं चल सकता था, मैंने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार आवश्यक पग उठाने की उद्घोषणा की। इस राज्य में इस समय चुनाव हो रहे हैं और आशा है यथा-शीघ्र साधारण वैधानिक प्रणाली से प्रशस्त कार्य फिर से चालू हो सकेगा।

आपको चतुर्थ संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करना होगा। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए और संविधान में दिए आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया है।

१९५५-५६ का भारत सरकार का आय और व्यय सम्बन्धी विवरण आपके सामने रखा जाएगा।

लोक सभा के पिछले सत्र के बाद एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया। इस अध्यादेश के बारे में एक विधेयक आपके सामने रखा जायगा। और बहुत से विधेयक भी विचारार्थ रहते हैं, जिन में से कुछ पर प्रवर समीक्षितों विचार कर चुकी हैं।

विगत वर्ष में हम ने जो उन्नति की है, उस से हमारे देशवासियों में भविष्य के प्रति आशा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकी है। भावी निर्माण का यही दृढ़ आधार है। संसद् के सदस्यगण, इस आशा को मूर्तिमान करना और देश को उसके निर्धारित लक्ष्य, अर्थात्

कल्याण राज्य की स्थापना, तक पहुँचाना तथा समाज का समाजवादी नक्शे के अनुरूप पुनर्गठन करना, आप लोग का कार्य है।

The President: Members of Parliament, I am addressing you again after a full year. This past year has been, I am glad to say, one of considerable achievement for our country, both in the domestic and the international spheres. Parliament and our people have justification to view their labours with some satisfaction. There is no reason, however, for complacency. We have to face difficult problems in our own country and the threat of war again darkens the future of humanity.

I am happy to say that our relations with all other countries continue to be friendly and there has been growing understanding and co-operation with many of them. We have had distinguished leaders of many countries visiting India. During the past year, we have had visits from the Prime Minister of Canada, Indonesia, China and Ceylon. We have also welcomed in India the President of the Federal People's Republic of Yugoslavia and the Governor-General of Pakistan. Our Vice-President has carried the messages of our goodwill to the United States, Canada, Mexico, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Brazil, Uruguay and Italy. My Prime Minister paid friendly visits to China, Burma, Indonesia, the States of Indo-China and Egypt. He has recently attended the Commonwealth Prime Ministers' Conference in London, where matters of vital concern to the peace of the world were discussed in a frank and friendly manner.

I should like to mention especially the agreement between China and India in regard to Tibet. This agreement confirmed the friendship between these two great countries, which is so important for the peace of Asia and the world. In this agreement certain principles were laid down which are of even wider application and which have been recognised as such by many other countries. These five principles, which are sometimes referred to as the Panch Shila, are mutual respect for

each other's territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful co-existence. I commend these principles to you and earnestly trust that they will increasingly form the basis of international relations, thus ensuring peace and security all over the world.

During this past year, another development of importance took place at the instance of the Prime Minister of Ceylon. This was the meeting of the Prime Ministers of Ceylon, Burma, Indonesia, Pakistan and India at Colombo. Later a similar meeting was held at Bogor in Indonesia. These meetings gave organised expression to the views and urges of these countries, which are a large part of Asia, and undoubtedly served the cause of peace. As a result of these meetings, it is now proposed to hold a conference in Indonesia consisting of representatives of the independent nations of Asia and Africa. This conference marks another stage in the development of the countries of these two great continents and in their emergence in the sphere of world affairs. It will, I am sure, bring greater understanding and co-operation among them and further the cause of world peace.

An outstanding event of the past year, and indeed ever since the second world war ended, was the Geneva Conference which brought an end to the war in Indo-China and laid the basis for a peaceful solution of the problems of the States of Indo-China. The Geneva Conference dealt with problems of great importance and difficulty but the efforts of the Powers concerned to find a peaceful solution met with success. That conference thus set an example, which I hope will be followed in future, for the settlement of other international disputes and conflicts.

As a result of the Geneva Conference, India has accepted heavy responsibilities in the three international Commissions appointed in Indo-China. These Commissions, under

[The President]

India's chairmanship, have already done good work in implementing the decisions reached at Geneva and deserve praise.

Unfortunately, other conflicts still continue, endangering the peace of the world. Among these, the most serious at the present moment is that relating to the Far East and, more particularly, to Formosa and the off-shore islands of China. My Government recognises only one government of China, that is, the People's Republic, and considers that the claims of this Republic are justified. I earnestly hope, however, that these difficult problems will be solved peacefully and by negotiation.

There is, indeed, no other way left for the solution of international disputes, if sanity is to prevail. Nuclear and thermo-nuclear weapons have been developed to such an extent that a war in which these are used would bring ruin to the world. No problem can be solved, no objective achieved, by this self-destruction of humanity. A Hydrogen-bomb not only destroys every living thing utterly within a large radius but also produces intense radio activity which will carry destruction to a much larger area. There is no defence against such weapons. Some eminent soldiers of different countries have stated categorically that a major war today, in which these weapons are used, has become unthinkable. I earnestly hope that the fearful nature of these weapons will lead not only to the total banning of their production but also to the realisation that war itself should be abolished as a means of settling any problem.

While atomic energy brings this threat of utter destruction to the world, it also gives a message of hope, provided it is used for peaceful purposes. Atomic energy provides the vast power necessary to raise the standard of living of the population of the entire world. It is of special importance for the development of the under-developed countries. We must welcome,

therefore, that the United Nations has decided to call a scientific conference on the peaceful uses of atomic energy at Geneva. This conference will not only explore the possibilities of atomic power but will also consider the biological, medical and agricultural aspects.

Another example of a peaceful negotiated settlement of a difficult problem is the *de facto* transfer to the Indian Union of the French possessions in India. We are happy to welcome the citizens of these territories. I would like to express my appreciation of the statesmanship of the French Government in dealing with this problem. I hope that the problem of the Portuguese possessions in India will also be settled before long in a peaceful way.

The economic situation in the country has shown continued and marked improvement. Many of the targets laid down by the Five-Year Plan were exceeded even in three years. The output of foodgrains in 1953-54 exceeded the Five-Year Plan target by about 4.4 million tons. The index of agricultural production which was 96 in 1950-51 rose to 114 in 1953-54. The index of industrial production which stood at 135 in 1953, the highest figure since independence, increased to 144 in 1954. This index has increased at an average rate of ten per cent. per annum during the last four years.

As a result of the improvement in production, many of the controls have been removed. The more abundant supply position of foodgrains created a tendency to depress prices unduly in certain surplus pockets. To prevent prices from falling to unremunerative levels, it has been decided to purchase certain foodgrains at specified prices.

My Government have decided to acquire effective control over the Imperial Bank of India in order, more especially, to afford increasing banking facilities in rural and under-developed areas. The establishment of the Indian Industrial Credit and Investment Corporation is expected to prove

of great benefit to the private sector of our industry.

Considerable progress has been made in the production of fertilisers at Sindri. The Hindustan Shipyard at Visakhapatnam delivered two eight thousand ton ships and launched another seven thousand ton ship in the course of the year. The Telephone Cable Factory at Rupnarainpur in West Bengal has gone into production. It has been designed to meet in full the requirements of the Posts and Telegraphs Department. The Penicillin Factory at Pimpri and the D.D.T. Factory at Delhi are about to commence production and it is proposed to establish another D.D.T. plant to meet the requirements of the Anti-Malaria campaign.

My Government attach great importance to increasing the iron and steel production in the country. With this end in view, two new steel plants, to be owned by the State, have already been decided upon. One is to be established at Rourekela. The other plant will be set up in the Bhilai region of Madhya Pradesh. A preliminary agreement, in regard to the latter, has been arrived at with the Government of the U.S.S.R.

My Government attach great importance, both from the point of view of production and of giving employment, to the growth of cottage and small-scale industries. With a view to introducing modern techniques in these industries, four regional institutes of technology are being established.

The great river valley schemes have shown considerable progress and a number of new projects are being started. In particular, I should like to draw attention to the public co-operation we are receiving in many of these projects. I would especially like to mention the great public response in respect of the Kosi project.

The Community Projects and the National Extension Service programme have already covered, in a little more than two years since its inauguration in October 1952, about one-fifth of the

rural population of India. At present, about 88,000 villages are being served by this programme which has achieved substantial results in agriculture and animal husbandry, public health, communications, education and irrigation. It is proposed to cover, by the end of the Second Five-Year Plan, the entire country by the National Extension Service. The most remarkable feature of this programme is the response and enthusiasm of the people who are beginning to acquire a new faith in themselves and the habit of working together on joint programmes for the common good.

There has been steady improvement in the rate of development and of expenditure under the Five-Year Plan, both at the Centre and in the States. Special measures have been taken for permanent improvement in areas affected by scarcity, in rural and urban water-supply schemes and in the electrification of rural areas and small towns.

The preparation of the Second Five-Year Plan has now begun. It is expected that this Plan will be a more far-reaching one than the First Plan, and that it will lay greater emphasis on the establishment of capital goods industries, on the provision of greater employment and on a re-orientation of the system of education.

A situation having arisen in the Andhra State in which the government of the State could not be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, I have taken necessary action by Proclamation in accordance with Article 356 of the Constitution. Elections are now being held in the State, and it is hoped that normal constitutional machinery will be restored before long.

You will have to consider the Constitution Fourth Amendment Bill. These amendments have become necessary in order to further economic and social progress and to give effect to the Directive Principles of State Policy as embodied in the Constitution.

A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government

[The President]

of India for the financial year 1955-56 will be laid before you.

Since the last session of Parliament, it became necessary to promulgate one ordinance. A bill dealing with this ordinance will be placed before you. There are also a considerable number of other bills pending, some of which have been considered by Select Committees.

The progress we have made during the past year has produced in our people self-reliance and hope for the future. That is the surest foundation on which we can build. It is for you, Members of Parliament, to give shape and form to this hope and to advance the country to its cherished goal of a Welfare State and a society conforming to the socialist pattern.

DEATHS OF SARVASHRI BORKAR, JAMNADAS MEHTA, SALVE AND SARDA.

Mr. Speaker: I have to inform the House of the very sad demise of four of our friends, namely Shri Nama Arjun Borkar, Shri Jamnadas Mehta, Shri P. K. Salve, and Shri Harbilas Sarda.

Shri Borkar who was about 29 years of age passed away as a result of an air crash near Nagpur airport, in the early hours of the 2nd February, 1955. He was elected from the Bhandara constituency, Madhya Pradesh, in May 1954, and was one of the leading Harijan workers. We are deeply shocked at this tragic loss.

Shri Jamnadas Mehta was a prominent Member of the old Central Assembly, and passed away on the 7th February 1955, in Bombay. He was 71 years of age.

Shri P. K. Salve was a Member of the old Central Legislative Assembly. He passed away at the age of 72 years in Nagpur on the 17th February, 1955.

Shri Harbilas Sarda was a well-known Member of the old Central Legislative Assembly. He passed

away in Ajmer on the 20th January, 1955, at the ripe age of 87 years. He was elected Member of the Central Legislative Assembly from Ajmer-Merwara in 1924, and was the Deputy Leader of the Nationalist Party in the Assembly. Shri Sarda was the author of the Child Marriage Restraint Bill, which has now come to be popularly known as Sarda Act.

We mourn the loss of these friends, and I am sure the House will join me in conveying our condolences to their families. The House may stand in silence for a minute to express its sorrow.

MOTION FOR ADJOURNMENT ELECTIONS IN ANDHRA

Mr. Speaker: I have received notice of an adjournment motion, which reads as under:

"The situation created in the course of General Elections in Andhra as a result of the failure of the Government to afford sufficient protection to voters in that State for exercising their franchise in a proper atmosphere free from intimidation and violence, as evidence in 5,000 voters being forcibly prevented from proceeding to polling booths in Nallamada constituency on 15th February, 1955, 1,200, voters being similarly obstructed in Challapalli constituency, smashing up of Communist Party's election offices in various constituencies, and Shri P. V. Raghavaiah, M.P., being attacked and assaulted at Ongole on 13th February, 1955."

I would like to know the facts from Government.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): If it suits your convenience and that of the House, I would suggest that perhaps this matter might be taken up tomorrow, when my colleague, the hon. Home Minister is here.